



सामंथा की मां इंटी बगारम का बनेगा सीक्वल

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मिली नई गति

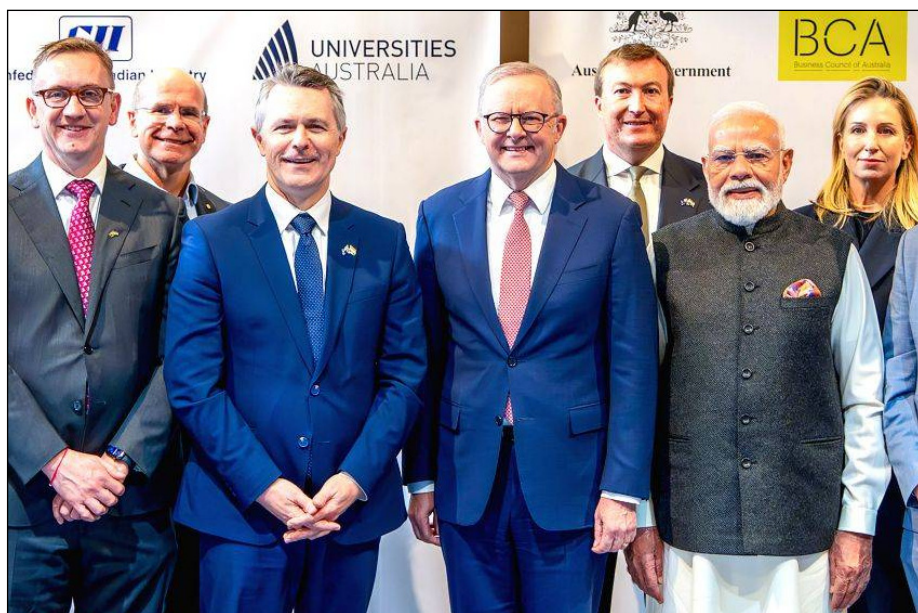
रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी सहित 18 प्रमुख समझौते

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत गुरुवार को रक्षा, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा विशेषकर नाभिकीय ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, खनन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक विरासत सहित विभिन्न क्षेत्रों में 18 महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों को अपनाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मेलबर्न में प्रधानमंत्री एथनी अब्बानीज के साथ सार्थक वार्ता की। वार्ता के नतीजों के तहत अब ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की सप्लाई होगी। ऑस्ट्रेलिया तीन प्राचीन कलाकृतियां भारत को लौटाएगा। रक्षा क्षेत्र में सहयोग में दोनों देशों ने कई नए विषयों को शामिल किया है।

दोनों नेताओं ने वार्ता के दौरान भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई मजबूत प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में बताया, हमने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी सीईसीए पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है।

प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में दोनों देशों की वैश्विक मुद्दों पर राय भी सामने रखी। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मानते हैं कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता



के लिए गंभीर चुनौती है। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई साझा और संकल्प अटूट है।

उन्होंने कहा कि हमारा यह भी मानना है कि विश्व के अनेक भागों में चल रहे तनावों और युद्धों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। पूरे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश मिलकर शांति, स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी एवं नवाचार साझेदारी के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने

पर भी सहमति व्यक्त की गई।

भारतीय कलाकृतियों एवं धरोहरों की वापसी के क्रम में कुछ और नाम जुड़े। ऑस्ट्रेलिया तमिलनाडु की तीन प्राचीन कलाकृतियों को वापस करेगा। इसमें शिव के वाहन पवित्र बैल नंदी (11वीं से 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट), शुभ काली (भद्रकाली) के साथ त्रिशूल (11वीं शताब्दी, कांस) एवं छह सिर वाले स्कंद (कार्तिकेय) (12वीं शताब्दी, बेसाल्ट) कलाकृति शामिल है।

दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौतों में संयुक्त रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग घोषणा का नवीनीकरण

शामिल है। इसके तहत सैन्य अंतर-संचालन क्षमता, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप, ऊर्जा सुरक्षा पर संयुक्त वक्तव्य, भारत-ऑस्ट्रेलिया असेन्य परमाणु समझौते के प्रशासनिक प्रबंध को अंतिम रूप तथा साइबर, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी (पीएसीटीएस) पर भी सहमति बनी। दोनों देशों ने भारतीय तटरक्षक बल और ऑस्ट्रेलियाई

भारत में 500 मिलियन डॉलर निवेश करेगा ऑस्ट्रेलियनसुपर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) में ऑस्ट्रेलियनसुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अतिरिक्त निवेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निवेश भारत की आर्थिक प्रगति और सुधारों पर वैश्विक निवेशकों के बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि ऑस्ट्रेलियनसुपर का नया निवेश भारत की विकास यात्रा में दुनिया के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि ये यह भारत की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में मौजूद विशाल निवेश अवसरों का भी प्रमाण है। इस निवेश की घोषणा मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक लीडर्स समिट के दौरान की गई। इस निवेश की घोषणा आज सुबह मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पॉल थ्रोडर ने किया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियनसुपर के सीईओ पॉल थ्रोडर ने 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के अतिरिक्त निवेश की जानकारी दी। अब इस निवेश के बाद भारत में सभी एसेट क्लास में ऑस्ट्रेलियनसुपर का कुल निवेश बढ़कर 3.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गया है। वर्ष 2015 में स्थापित नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) का उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दीर्घकालिक संस्थागत निवेश को आकर्षित करना है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलियनसुपर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी और प्राइवेट मार्केट में लगभग 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का निवेश कर चुका है।

मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच सहयोग बढ़ाने, वर्ष 2028-29 में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज में भारतीय सैन्य प्रशिक्षक की नियुक्ति से जुड़े समझौते भी किए हैं।

शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में खनन एवं खनन उपकरण उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। फिल्लंड्स विश्वविद्यालय बेंगलुरु में कैपस

स्थापित करेगा। इसके अलावा विकटोरिया विश्वविद्यालय गुडगांव में अपना शिक्षा परिसर बनाएगा। व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, वैज्ञानिक अनुसंधान, भू-विज्ञान, पारंपरिक ज्ञान, फिल्म शिक्षा तथा नवाचार के क्षेत्र में भी कई समझौते किए गए। गांधीनगर में रूफटॉप सौर प्रशिक्षण अकादमी को ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संचालन में लाकर हरित ऊर्जा क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा।



राम मंदिर ट्रस्ट ने रिकॉर्ड और तस्वीरों की जारी

अयोध्या, एजेंसी। अयोध्या के राम मंदिर को वर्ष 2021 में दान की गई 200 किलो चांदी को लेकर उठे सवालोंने पर अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक जवाब जारी कर दिया है। ट्रस्ट ने कहा है कि दान में मिली पूरी चांदी का रिकॉर्ड सुरक्षित है और उसे नियमानुसार संरक्षित रखा गया है।

दरअसल, विश्व सिंधी सेवा संगम ने कुछ दिन पहले ट्रस्ट को एक पत्र भेजकर पूछा था कि 26 जनवरी 2021 को दान की गई 200 चांदी की ईंटों का क्या हुआ। संगठन का कहना था कि दान देने वाले लोगों को अब तक न तो इसकी आधिकारिक रसीद मिली है और न ही यह जानकारी दी गई कि मंदिर निर्माण या अन्य कार्यों में इस चांदी का इस्तेमाल कहाँ किया गया। इसी वजह से संगठन ने ट्रस्ट से पूरे मामले में स्पष्ट जानकारी मांगी थी।

ट्रस्ट ने अपने जवाब में बताया कि दान में मिली सभी 200 चांदी की ईंटों का विवरण ट्रस्ट के मूल्यवान धातु रजिस्टर में दर्ज है। ट्रस्ट के अनुसार, बाद में लिए गए एक निर्णय के तहत इन ईंटों के साथ अन्य उपलब्ध चांदी को भी पिघलाकर 99.99 प्रतिशत शुद्धता

वाली 20-20 किलोग्राम की सिल्वर बार तैयार कराई गई। ट्रस्ट का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार की गई।

अपने दावे के समर्थन में ट्रस्ट ने कुछ तस्वीरों भी साझा की हैं। इन तस्वीरों में चांदी का वजन, उसे पिघलाने की प्रक्रिया और तैयार की गई सिल्वर बार दिखाई गई हैं। ट्रस्ट ने बताया कि फिलहाल ये सिल्वर बार भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा के लॉकर में सुरक्षित रखी गई हैं। भविष्य में ट्रस्ट की आवश्यकताओं और मंदिर से जुड़े कार्यों में इनका उपयोग किया जाएगा। ट्रस्ट ने विश्व सिंधी सेवा संगम से यह भी अनुरोध किया है कि वह सभी 200 दानदाताओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर, पैन और ईमेल की जानकारी उपलब्ध कराए। ट्रस्ट का कहना है कि यह जानकारी मिलने के बाद प्रत्येक दानदाता के नाम से अलग-अलग आधिकारिक रसीद जारी की जाएगी। इस तरह, दान में मिली 200 किलो चांदी को लेकर उठे सवालोंने पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दस्तावेजों, तस्वीरों और आधिकारिक जानकारी के साथ अपना पक्ष सार्वजनिक कर दिया है।

जंतर-मंतर पर सीजेपी का 20 दिनों से धरना जारी

भारी बारिश के बीच सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद मार्च का किया आह्वान

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश के बावजूद जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) का धरना गुरुवार को 20वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी तिरपाल और बरसाती का सहारा लेकर डटे हुए हैं और अपनी मांगों के समर्थन में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस आंदोलन के मुख्य चेहरा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आंदोलनकारी मुख्य रूप से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं, जबकि भूख हड़ताल पर बैठे एक छात्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनम वांगचुक का अडिग संकल्प सोनम वांगचुक ने अपने समर्थकों और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल अनशन



समाप्त करने से छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों, शिक्षा प्रणाली और भविष्य की पीढ़ियों की है।

उन्होंने शिक्षा के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और कहा कि यदि समय रहते नीतियां नहीं बदली

गई, तो हिमालय और भारत की नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

संसद तक शांतिपूर्ण मार्च की तैयारी आंदोलन को और व्यापक बनाने के लिए सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचने और संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकालने का आह्वान किया है। उन्होंने देश के युवाओं और जागरूक नागरिकों

से अपील की कि वे केवल सोशल मीडिया तक सीमित न रहें, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से मैदान में आकर भागीदारी सुनिश्चित करें। वांगचुक का मानना है कि सामूहिक जनभागीदारी से ही सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है और शिक्षा व पर्यावरण जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई ठोस समाधान निकाला जा सकता है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सख्त हुए गडकरी

अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए

○ अलवर में ढाबे हटाने, अतिक्रमण पर कार्रवाई और सड़क सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश

अलवर, एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को अलवर जिले के पिनान रेस्ट एरिया पहुंचकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता, सड़क सुरक्षा और लगातार हो रही दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

राजस्थान में प्रवेश पर पिनान रेस्ट एरिया में उपमुख्यमंत्री दिया कुमार ने केंद्रीय मंत्री का बुके भेंट



कर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर आर्तिश शुकला, पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। करीब एक घंटे तक पिनान

रेस्ट एरिया में रुके केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा और इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने हाल के सड़क हादसों के कारणों की जानकारी लेते हुए सड़क की

गुणवत्ता को तकनीकी रूप से और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

गडकरी ने स्पष्ट कहा कि एक्सप्रेसवे पर बने अवैध ढाबों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हाईवे पर खड़े ट्रकों को तत्काल हटाया जाए तथा सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क पर गड़बड़ या क्षतिग्रस्त हिस्सों की तत्काल मरम्मत हो, नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सड़क सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाने, पुलिस गश्त नियमित रखने तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए।



INDIAN AIR FORCE

AGNIVEER (VAYU 02/2027)

RECRUITMENT 2026

SERVE THE NATION • SOAR WITH PRIDE

IMPORTANT DATES

- Notification Out : 17/06/2026
- Starting Date : 06/07/2026
- Last Date : 26/07/2026 11:00 PM
- Exam Date : 22-23 September 2026
- Admit Card : Available Soon

APPLICATION FEES

For All Candidates

₹550/- + GST

Payment Mode

ONLINE MODE

AGE LIMIT DETAILS

Age Limit

17.5 - 22 Years

Born Between

01/07/2005 To 01/01/2010
(Both Dates inclusive)

SELECTION PROCESS

- Online Written Exam
- Physical Fitness Test (PFT)
- Adaptability Test-I
- Adaptability Test-II
- Medical Examination
- Document Verification

MONTHLY SALARY DETAILS

- 1st Year : ₹30,000/-
- 2nd Year : ₹33,000/-
- 3rd Year : ₹36,500/-
- 4th Year : ₹40,000/-

TOTAL POST & QUALIFICATION

Agniveervayu (Science Subjects) POST Not Given

12th Passed with Mathematics, Physics, and English (50% Marks) OR 03 Years Diploma in Engineering, Only Unmarried Candidates are Eligible.

Agniveervayu (Other Than Science Subjects) POST Not Given

12th Passed in any Stream with (50% Marks), Only Unmarried Candidates are Eligible.

PHYSICAL ELIGIBILITY DETAILS

Type	Male	Female
Height	152 CMS	152 CMS
Chest	77-82 CMS	As Per Rule
Race (1.6 KM)	1.6 KM in 07 Mins	1.6 KM in 08 Mins
Push-ups	10 in 01 Minute	NA
Sit-ups	10 in 01 Minute	10 in 01.30 Minute
Squats	20 in 01 Minute	15 in 01 Minute

EXAM PATTERN & SYLLABUS

Exam Mode : Online (CBT)
Marking Scheme : 1 Mark For Each Correct Answer
Negative Marking : 1/4th Mark

SCIENCE SUBJECTS

60 MINUTES

The total duration of the online test shall be 60 minutes and shall comprise English, Physics, and Mathematics as per the 10+2 CBSE syllabus.

OTHER THAN SCIENCE SUBJECTS

45 MINUTES

The total duration of the online test shall be 45 minutes and shall comprise English as per the 10+2 CBSE syllabus and Reasoning & General Awareness.

SCIENCE SUBJECTS & OTHER THAN SCIENCE SUBJECTS

85 MINUTES

The total duration of the online test shall be 85 minutes and shall comprise English, Physics, and Mathematics as per the 10+2 CBSE syllabus and Reasoning & General Awareness (RAG).

DISCIPLINE ★ DEDICATION ★ DETERMINATION ★ EXCELLENCE

JOIN THE FORCE, BE THE FUTURE

Note : Read the official notification carefully before applying. For more details visit : www.indianairforce.nic.in

सम्पादकीय

उत्तरप्रदेश की राह पर बंगाल

प.बंगाल में भाजपा शासन के आते ही राज्य में चारित्रिक बदलाव दिखाई देना शुरू हो चुका है। भाजपा शासन की खास पहचान बन चुके बुलडोजर और पुलिस मुठभेड़ दोनों का इस्तेमाल प.बंगाल में शुरू हो चुका है। सुवेन्द्र अधिकारी के सत्ता संभालते ही तुषमूल कांग्रस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई, कई मौकों पर जनता ने कानून हाथ में लिया और टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंके। भाजपा ने इसे लोगों का गुस्सा बताकर न्यायोचित ठहराने की कोशिश की। कई बाजारों में रेहड़ी-पटरी वालों को जबरन हटाय़ा गया और कुछ जगह बुलडोजर से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को गिराया गया। और अब बारुईपुर मामले में एक अहम आरोपी की मुठभेड़ में मौत हो गई, जिससे प.बंगाल को भाजपाई रंग में ढलने में जो कसर बाकी थी, वह भी पूरी हो गई।

गौतलब है कि बीते दिनों कोलकाता के दक्षिणी उपनगर स्थित बारुईपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद नृशंसा से हत्या कर दी गई। ऐसी एक भी घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए बड़ा कलंक होनी चाहिए। जो समाज अपने बच्चों की, महिलाओं की हिफाजत न कर सके, उसे शर्मिंद होना चाहिए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि बलात्कार जैसा गंभीर अपराध अब राजनीति करने का जरिया बन चुका है। जब प.बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के वक्त आर जी कर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या का मामला आया था, तब भाजपा ने बिना समय गंवाएं टीएमसी सरकार को घेरा, राज्य में धरना-प्रदर्शन सब किया। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई की, आरोपियों को पकड़वाया, फिर भी उन पर ऊंगली उठाई गई कि वे बहन-बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती। इस चुनाव में भी भाजपा ने इस मुद्दे को धुनाचा चाहा और इसके लिए आर जी कर मेडिकल कॉलेज को दिवंगत पीड़िता की मां को टिकट दी, वे जीतीं और अब विधायक भी बन गई हैं। लेकिन अफसोस है कि वे भी अब पीड़ित परिवार के साथ खुलकर खड़े होने और ऐसे नृशंस अपराध पर आवाज उठाने की जगह खोखले तर्क दे रही हैं कि मेरी बेटी के साथ अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह पर ऐसा हुआ, जबकि वो बच्ची बाहर थी या कहां थी, पता नहीं। इस बयान के बाद सभ्य समाज को अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि क्या बच्चे केवल अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं, बाहर नहीं। अगर ऐसा है तो हम किस अधिकार से खुद को सभ्य कहते हैं। और कई मामलों में घर में करीबी रिश्तेदार ही जो शारीरिक शोषण करते हैं, उस वक्त बच्चों के लिए कौन सा सुरक्षित स्थान बताया जाएगा। जाहिर है भाजपा विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ या नयी सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ खुल कर बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो उन्होंने सारा ठीकरा पिछली टीएमसी सरकार पर फोड़ दिया। हालांकि इसकी कोई तुक बनती नहीं। अगर ममता बनर्जी की सरकार लड़कियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में नाकाम थी, तो जनता ने उनको नई सत्ता से हटा दिया है। अब जिनकी सत्ता है, यानी भाजपा की, तो उसे हर तरह से जिम्मेदारी लेना होगा।

लगता नहीं मामला मैनेज हो पाएगा!

अरविन्द मोहन

जो खबरें आई हैं उनके अनुसार मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख नृत्य गोपाल दास समेत सभी सदस्य बहुत गुस्से में थे लेकिन किया इतना ही कि इस्तीफा दे चुके सदस्यों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। शायद इसे न मानने का प्रावधान भी नहीं है। उधर मुख्य कर्ताधर्ता चंचत राय यह संकल्प दोहराते घूम रहे हैं कि वे यह अपयश लेकर अयोध्या से वापस नहीं जाएंगे। उनके पक्ष में कथित संत समाज के कुछ लोग खुला समर्थन घोषित करने लगे हैं।

राममंदिर के चढ़ावा में चोरी के लगभग सत्तर मामलों में पक्के सबूत मिलने के बाद भी मंदिर ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित एसआईटी की कार्रवाई का पहला दौर बीत जाने के बाद भी खरीसा नहीं रहा है कि मामले के दोषियों को सजा मिल पाएगी या असली अपराधी और मंदिर आंदोलन के असली लाभाधीयों का कभी बाल भी बांका हो पाएगा। इतना जरूर होगा कि कुछ दोषी पकड़े जाएंगे और शायद थोड़ी सजा भी पा जाएंगे। यह भी होगा ही कि आगे से प्रबंधन थोड़ा ज्यादा चौकस होगा और विश्व हिन्दू परिषद को चन्दा संबंधी गड़बड़ी पर नोटिस देने वाले विश्वबंधु गुप्त को परेशान करने से लेकर अयोध्या में जमीन रजिस्ट्री के स्पष्ट घोटाले जैसे मामले सामने आने पर आंख बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन आम लोगों के नजरिया से हुए इस महापाप की सजा, प्रार्थक्षित और मंदिर आंदोलन के 'पुण्य-प्रताप' से सत्ता में बैठने और मामालाल होने वालों तक इस कांड की आंच पहुंचेगी इसकी संभावना कम ही लगती है। सारा कुछ राजनीतिक नुकसान कम करने के प्रबंधन से जुड़ा लग रहा है। अभी तक एक भी कदम दोषियों को पकड़ने और सजा दिलाने की तरह ठोस उठाया नहीं लगता-बुलडोजर चलना और इनकाउंटर करने का यूपी का मॉडल लागू करने का तो कोई वकालत भी नहीं कर सकता।

जो खबरें आई हैं उनके अनुसार मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख नृत्य गोपाल दास समेत सभी सदस्य बहुत गुस्से में थे लेकिन किया इतना ही कि इस्तीफा दे चुके सदस्यों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। शायद इसे न मानने का प्रावधान भी नहीं है। उधर मुख्य कर्ताधर्ता चंचत राय यह संकल्प दोहराते घूम रहे हैं कि वे यह अपयश लेकर अयोध्या से वापस नहीं जाएंगे। उनके पक्ष में कथित संत समाज के कुछ लोग खुला समर्थन घोषित करने लगे हैं और एसआईटी ने उनको और उनके चले की बरी ही कर दिया। पहली नजर में यह मामला आरोपी द्वारा खुला घूमने की स्थिति का लाभ लेने का लगता है और वे जांच या दंड प्रक्रिया को प्रभावित करते दिखते हैं। अजीब यह है कि कोषाध्यक्ष महाराज भी खुलेआम कह रहे हैं कि उनको चढ़ावा और चन्दा से कोई लेना-देना नहीं रहा है। एक और वरिष्ठ गुप्तेन्द्र मिश्र सब कुछ बताने पर प्रकट हुए और ऐसा बयान दिया जैसे इस प्रकरण से उनका कोई लेना-देना ही नहीं है। संसद में नया कानून बनाकर मंदिर का नया प्रशासन देने वाले या उत्तर प्रदेश में शासन संभालने और रामराज्य लाने का दावा करने वाले दूध का दूध और पानी का पानी करने के अलावा ज्यादा कुछ करते नरहीं आये हैं। चोरी का मामला सामने आने के बाद एसआईआर दर्ज कराने से लेकर एसआईटी में ट्रस्ट प्रशासन के लोगों को रखने और जांच की अवधि बढ़ाने जैसी बुनियादी गलतियों को अगर आप चुक मान लेंगे तो आपसे इस बड़े अनेतिक अपराध की गंभीरता और उसके प्रायश्चित और सजा के प्रसंग में उससे भी बड़ी चुक हो जाएगी। असल में यह मान-मनव्यल से रिकवरी करा कर मामले को रफा-दफा कराने और दोषियों को थोड़ा बहुत डांट-फटकार देने का प्रयास हो सकता है। कल जो दान के कीमती सामान प्रदर्शित हुए उसमें कुछ इसी तरह रिकवर हुए हो सकते हैं। चोरी के ठोस प्रमाण के बाद अपराधियों को खुला छोड़ना और बाद में कुछ को पुलिस रिमांड की जगह न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला इसी के चलते हुआ होगा। अभी भी ट्रस्ट किस अधिकार से अपनी कार्यपद्धति में बदलाव और सीईओ जैसा पद बनाने का फैसला कर रहा है यह साफ नहीं है। हम जानते हैं कि पंद्रह दिन में फैसला होने की अवधि किस तरह बढ़ती गई है और अब ट्रस्ट दोबारा पंद्रह दिन बाद बैठेगा तब तक उस पर काफी कुछ धूल बैठ चुकी होगी। जिस तरह विनय कटियार जैसे लोग एक दिन एक सूर में बोलते हैं और अगले दिन पलट जाते हैं। यह मैनेजमेंट की संघ की स्टाइल है। संघ और भाजपा का मैनेजमेंट स्टाइल अब अनजान भी नहीं है। और उसमें किन-किन चीजों का प्रयोग होता है और हो सकता है यह अज्ञात नहीं है। लेकिन इस बार एक खास बात है। इस बार असली नाराजगी उन साधु संतों में है जिनको राम के नाम से तो मतलब है लेकिन जिनको सत्ता और राजनीति से कोई खास मतलब नहीं है। उनको धन का भी वैसा मोह नहीं है। अब यह जरूर है कि उनकी सहमति से ही अब तक मंदिर आंदोलन में भाजपा शामिल हुई थी और इससे आंदोलन बड़ा हुआ और मंदिर निर्माण संभव हुआ।

सर्वीमित्रा सुरजन

दुनिया में हमेशा सात अजूबों की ही बात होती है। भारत तो इन अजूबों का सबसे बड़ा दावेदार है, क्योंकि हमारे पास ताजमहल है, जिसे अजूबा मानकर ही दुनिया भर के सैलानी देखने आते हैं और देखते रह जाते हैं। लेकिन मुगलों की बनाई इस नायाब कृति को पछाड़ने का काम नरेंन्द्र मोदी करने जा रहे हैं। सात अजूबों के बाद अब वो आठवें अजूबे के प्रबल दावेदार हो गए हैं। इस गणित को समझना कठिन नहीं है। अगर नरेंन्द्र मोदी से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि आठ से उनका रिश्ता कितना पुराना है। इस रिश्ते को समझा कर वे अल्बर्ट आइंस्टीन को भी पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का आठवां अजूबा है। जो इसे समझता, वह चुकता है। अब भारत के लोग बेचारे कर्ज के बोझ में तो ऐसे खेहे हुए हैं कि उनके लिए हर तरह का ब्याज चक्रवृद्धि की तरह ही है। जब तक उन्हें पता चलता है कि हमने इस महीने इतने रुपए कमाए हैं, तब तक उससे कहीं ज्यादा का खर्च मोदी सरकार उनके सामने खड़ा कर देती है। आईस्टीन ने मोदी का शासन नहीं देखा था, वरना वो चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं मोदी शासन के तौर तरीकों को आठवां अजूबा बता देते और शायद इस देश की जनता को नौवां अजूबा, जो सारे जुल्मो-सितम और तकलीफों के बावजूद इस आस में है कि अच्छे दिन आयें। अगर अच्छे दिन आने

सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में भी मोदी के लिए आठ की संख्या ने बड़ा योगदान दिया है। 26 जनवरी 2001 को भुज में विनाशकारी भूकंप आया था। जोड़ आठ का ही बनता है। उस समय केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस त्रासदी के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई, फिर वो सत्ता से हटे।

दुनिया में हमेशा सात अजूबों की ही बात होती है। भारत तो इन अजूबों का सबसे बड़ा दावेदार है, क्योंकि हमारे पास ताजमहल है, जिसे अजूबा मानकर ही दुनिया भर के सैलानी देखने आते हैं और देखते रह जाते हैं। लेकिन मुगलों की बनाई इस नायाब कृति को पछाड़ने का काम नरेंन्द्र मोदी करने जा रहे हैं। सात अजूबों के बाद अब वो आठवें अजूबे के प्रबल दावेदार हो गए हैं। इस गणित को समझना कठिन नहीं है। अगर नरेंन्द्र मोदी से पूछेंगे तो वो बता देंगे कि आठ से उनका रिश्ता कितना पुराना है। इस रिश्ते को समझा कर वे अल्बर्ट आइंस्टीन को भी पीछे छोड़ देंगे, जिन्होंने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का आठवां अजूबा है।

राजेन्द्र शर्मा

चुनाव आयोग की विवादस्पद भूमिका के संबंध में जहां स्वाभाविक रूप से विधानसभाई चुनावों के हाल के चक्र में और विशेष रूप से प. बंगाल तथा असम में उसके अनेक विवादस्पद निर्णयों की ओर इशारा किया गया है, वहीं आयोग के जिस एक निर्णय की इस संयुक्त पत्र में अपेक्षाकृत विस्तार से चर्चा की गयी है, वह है मतदाता सूचियों का विशेष सघन पुनरीक्षण।

देश की 23 विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त रूप से चिड़्डी लिखकर देश के सर्वोच्च न्यायालय से देश में जनतंत्र को बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की गुहार लगायी है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह शायद पहला ही मौका है, जब विपक्ष ने इस तरह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटया है। विपक्ष के इस कदम में, एक प्रकार की लाचारी भी छुपी है। चिड़्डी का अंत इस यथार्थ स्थिति के बयान पर होता है कि अगर इस अदालत के दरवाजे से भी न्याय नहीं मिलता है, तो शायद हिस्से के लिए खटखटाने के लिए और कोई दरवाजा ही नहीं रह जाएगा! याद रहे कि जिन विश्वीषी पार्टियों ने मिलकर यह गुहार लगायी है, संसद में भले ही अल्पमत में हों, पर वास्तव में जनमत के सत्ता पक्ष के मुकाबले कुछ न कुछ बड़े हिस्से का ही प्रतिनिधित्व करती हैं, छोटे हिस्से का नहीं। जनमत के उल्लेखनीय हिस्से की इस गहरी चिंता से इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी राज में भारत में जनतंत्र पर

कितना भारी खतरा छाया हुआ है।

हेराना की बात नहीं है कि विपक्षी पार्टियों की इस चिड़्डी में सबसे प्रमुख रूप से चुनाव आयोग की भूमिका का सवाल उठाया गया है, जिनमे जनतांत्रिक चुनाव के निष्पक्ष ण्यापक की अपनी संविधान में अनेकभूमिका का शरीरब-करीब त्याग ही कर दिया है और एक तरह से सत्ताधारी टीम में ही शामिल हो गया है। इस संदर्भ में चिड़्डी में अपने बहुमत के बल पर, एक किस तरह, अनुप बरनवाल बनाम भारतीय संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ही संसदीय पीठ ने, चुनाव आयोग की कार्यपालिका से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के पक्ष में जो फैसला दिया था और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देश के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के तीन सदस्यीय पैनल द्वारा मुक्त चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किए जाने का जो आदेश दिया था, उसे मोदी राज ने संसद में अपने बहुमत के बल पर, एक नया कानून लाकर पूरी तरह से ही उलट दिया। अब तीन सदस्यीय पैनल में से मुख्य न्यायाधीश को हटाकर, उनकी जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा नामजद करने एक मंत्रिमंडलीय सहयोगी को लाया जा चुका है और इस तरह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका है। नतीजा यह है कि आज चुनाव आयोग की भूमिका कि मोदी राज में भारत में जनतंत्र पर

कभी भी नहीं थी।

चुनाव आयोग की विवादस्पद भूमिका के संबंध में जहां स्वाभाविक रूप से विधानसभाई चुनावों के हाल के चक्र में और विशेष रूप से प. बंगाल तथा असम में उसके अनेक विवादस्पद निर्णयों के ओर इशारा किया गया है, वहीं आयोग के जिस एक निर्णय की इस संयुक्त पत्र में अपेक्षाकृत विस्तार से चर्चा की गयी है, वह है मतदाता सूचियों का विशेष सघन पुनरीक्षण कराने का चुनाव आयोग का इकतर्फा फैसला। याद रहे कि मतदाता सूचियों को शुद्धता सुनिश्चित करने के नाम पर, चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले हड़बड़ी में जब यह प्रक्रिया शुरू की गयी थी, तभी से इस प्रक्रिया की जरूरत, उपयुक्तता तथा वैधता पर सवाल उठ रहे थे। जिस तरह लगभग असंभव समय की सीमाओं के साथ, मतदाता सूचियां लगभग नये सिरे से तैयार कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस हड़बड़ी के अलावा और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से, इस पूरी प्रक्रिया को दस्तावेजी साक्ष्यों के सहारे नागरिकता पंशक्षण यानी पिछले दरवाजे का राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर थोपे जाने में तब्दील किए जाने पर, शुरू से गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे।

बहरहाल, इन सभी सवालों को इस झूठे सांप्रदायिक प्रचार से दबाने की कोशिश की कि यह कसतत वास्तव में

मोदी ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो हरेक के खाते में 15-15 लाख डालूंगा, तो लोगों ने उनकी बात का यकीन कर लिया था। अब 15 लाख नहीं आए तो दोष मोदी पर डाल रहे हैं कि वादाखिलाफी की। लेकिन गौर से देखें तो इसमें जनता के गणित के कमजोरी निकली। 15 यानी एक और पांच का जोड़ छह होता है। अंग्रेजी में छह लिखें तो तुम्हारा छह मेरा नौ या मेरा छह तुम्हारा नौ हो सकता है। जिस संख्या में यही तय न हो कि वो असल में क्या है, उसे लेकर कही किसी भी बात पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। मोदी ने तो जनता के यकीन और समझदारी की परीक्षा ली, जिसमें जनता फेल हो गई। अब ये कोई नीट पेपर लीक का मामला तो है नहीं कि बार-बार उसे कराया जाए। इसलिए अब 15 लाख वाली बात को जुमला बोलकर अमित शाह ने ठंडे बस्ते में डालने का पुण्य काम किया है। मोदी अगर कहते कि मैं सबके खाते में 17-17 लाख डालूंगा, तब उनसे सवाल किए जाने थे।

वैसे आठ से मोदी का रिश्ता केवल गणतंत्र दिवस और जन्मदिन तक सीमित नहीं है। वो अपने कार्यकाल की शुरुआत से इसे निभाते आ रहे हैं। मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, यहां भी जोड़ आठ बैठा। इसमें आठ देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी, पाकिस्तान से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका से राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, अफगानिस्तान से राष्ट्रपति हाamid करज़ई, नेपाल से प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, भूटान से प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे, मालदीव से राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन, बांग्लादेश से संसद की स्पीकर शिरिन शर्मिन चौधरी और मॉरीशस से प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साक्षी बने। मोदी ने नोटबंदी का फैसला 8

नवंबर को ही लिया। जब राष्ट्र के नाम संबोधन करना हो तो मोदी रात आठ बजे का वक्त ही चुनते थे। पिछले कुछ बार से इसमें तब्दीली आई है वरना आठ से मोदी का रिश्ता तोड़ना कठिन था।

सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में भी मोदी के लिए आठ की संख्या ने बड़ा योगदान दिया है। 26 जनवरी 2001 को भुज में विनाशकारी भूकंप आया था। जोड़ आठ का ही बनता है। उस समय केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस त्रासदी के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई, फिर वो सत्ता से हटे और अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने मोदी पहली बार विधायक बने। इस संख्या के जोड़ में अतिरिक्त दो आ गया है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे मोदी ने एक्स्ट्रा 2 एबी का फामुल्रा कनाडा में बताया था। ये भी मोदी की राजनैतिक दूरदर्शिता ही है कि आठ के अंक के अलावा 2 एक्स्ट्रा साथ में रखे, न जाने कब कहां कौन सा फामुल्रा फिट करने की जरूरत पड़ जाए। विश्वगुरु मोदी के लिए नए फामुल्रे गढ़ना तो बाएं हाथ का काम है। अपनी बुद्धि से प्रधानमंत्री अमेरिका में भी दिखा चुके हैं। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोलते रह गए, मोदी ने फौरन उसमें फिट होने का प्लान तैयार किया, और कह दिया कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, फिर मांगा और मीगा को मिलाकर मेगा कैसे बनता है, ये सधि ट्रंप को समझा दी। आठ का गणित आज भी काम कर गया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में चार शब्द हैं और मेक इंडिया ग्रेट अगेन में भी चार, चार और चार आठ होते हैं।

एसआईआर: कमजोर पर वार!

चुनाव आयोग की विवादस्पद भूमिका के संबंध में जहां स्वाभाविक रूप से विधानसभाई चुनावों के हाल के चक्र में और विशेष रूप से प. बंगाल तथा असम में उसके अनेक विवादस्पद निर्णयों के ओर इशारा किया गया है, वहीं आयोग के जिस एक निर्णय की इस संयुक्त पत्र में अपेक्षाकृत विस्तार से चर्चा की गयी है, वह है मतदाता सूचियों का विशेष सघन पुनरीक्षण कराने का चुनाव आयोग का इकतर्फा फैसला। याद रहे कि मतदाता सूचियों को शुद्धता सुनिश्चित करने के नाम पर, चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले हड़बड़ी में जब यह प्रक्रिया शुरू की गयी थी, तभी से इस प्रक्रिया की जरूरत, उपयुक्तता तथा वैधता पर सवाल उठ रहे थे। जिस तरह लगभग असंभव समय की सीमाओं के साथ, मतदाता सूचियां लगभग नये सिरे से तैयार कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस हड़बड़ी के अलावा और उससे भी महत्वपूर्ण रूप से, इस पूरी प्रक्रिया को दस्तावेजी साक्ष्यों के सहारे नागरिकता पंशक्षण यानी पिछले दरवाजे का राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर थोपे जाने में तब्दील किए जाने पर, शुरू से गंभीर सवाल उठाए जा रहे थे।

बहरहाल, इन सभी सवालों को इस झूठे सांप्रदायिक प्रचार से दबाने की कोशिश की कि यह कसतत वास्तव में मतदाता सूचियों से 'विदेशियों' को छानकर निकालने के लिए जरूरी थी। लेकिन, जब बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गयी, इस प्रक्रिया में छनकर निकले 'विदेशियों' की संख्या सैकड़ों तो क्या दर्जनों में भी नहीं थी, जिसकी वजह से पत्रकारों के बार-बार पूछने के बावजूद, चुनाव आयोग से यह बताते नहीं बना कि बिहार में कितने विदेशी नागरिक मतदाता बने पाए गए थे। इसलिए, एसआईआर के 5 फीसद के देश के करीब आधे राज्यों पर, जिनमें इसी साल के पूर्वाद्ध में विधानसभाई चुनावों की तैयारी कर रहे बंगाल समेत चार राज्य तथा एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, न सिर्फ एसआईआर थोप दिया बल्कि एक और केंद्रीय सत्ता व सत्ताधारी संघ-भाजपा और दूसरी ओर चुनाव आयोग की जुगलबंदी के सहारे, एसआईआर की प्रक्रिया को 'घुसपैठियों' को निकालने के लिए मतदाता सूचियों की गहरी 'छानाई' के रूप में पेश किया जाना जारी रहा।

बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से यह ध्यान दिलाया जा रहा था कि दस्तावेजी साक्ष्यों से नागरिकता को प्रमाणित करने को प्राथमिकता देने वाली यह प्रक्रिया, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर तबकों यानी भूमिहीनों, अनपढ़ों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि को, मतदाता सूचियों से बाहर करने और उनका मताधिकार छीनने का काम करेगी। और ठीक यही हुआ

शुरू हुई, तभी से यह ध्यान दिलाया जा रहा था कि दस्तावेजी साक्ष्यों से नागरिकता को प्रमाणित करने को प्राथमिकता देने वाली यह प्रक्रिया, आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर तबकों यानी भूमिहीनों, अनपढ़ों, दलितों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि को, मतदाता सूचियों से बाहर करने और उनका मताधिकार छीनने का काम करेगी। और ठीक यही हुआ

जुड़ने के बजाय, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लगातार एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। क्वाड और भारत-प्रशांत रणनीति जैसे ढांचे के अंदर भी भारत अमेरिका के साथ एक औपचारिक सहयोगी या कनीय सुरक्षा भागीदार के बजाय एक बराबर के भागीदार के तौर पर जुड़ना चाहता है।

ऑफिशियल मीडिया में चीनी विशेषज्ञ की इस टिप्पणी से पता चलता है कि चीन अब भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध को बेहतर बनाने के लिए भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है और अपने पहले के इस रूख को नरम कर दिया है कि अमेरिका ने अपनी भारत-प्रशांत रणनीति में भारत को एक भागीदार के तौर पर लिया है, जो मुख्य रूप से चीन के खिलाफ थी। चीनी विश्लेषक का जोर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दबाव को नज 7अंदाज करते हुए एक स्वतंत्र नीति अपनाने की कोशिश कर रहे थे।

चीनी विशेषज्ञ के मुताबिक लैंडाऊ की बातें भारत के प्रति वॉशिंगटन के बड़े दृष्टिकोण को दिखाती हैं, और वह है भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा में नई दिल्ली का समर्थन मांगते हुए उसे औद्योगिक श्रृंखला के निचले सिरे पर लॉक करना। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी रणनीति भारत के अर्थशास्त्रिक लक्ष्यों के खिलाफ है।

कियानोफेंग के अनुसार, 'उद्योगीकरण सभी विकासशील देशों का एक कानूनी अधिकार है। जीरो-सम सोच (एक का

भी। हालांकि, आश्काओं के विपरीत, मुसलम अल्पसंख्यकों की बहुत बड़ी संख्या को बाहर नहीं किया जा सका और दूसरी ओर, प्रवासी मजदूरों की खासतौर पर बड़ी संख्या पर इस छटाई की गाज गिरी, फिर भी इस प्रक्रिया में जो 65 लाख नाम मतदाता सूचियों से हटाए गए, उनमें से मुत्तकों की श्रेणी के 22 लाख और एक से ज्यादा जगह नाम की श्रेणी के 7 लाख नामों को छोड़ भी दें तो, 36 लाख यानी कुल मतदाताओं के 5 फीसद से ज्यादा के नाम, उनके जिंद होते हुए काट दिए गए। इनमें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर तबकों के यानी भूमिहीनों, अनपढ़ों, दलितों, महिलाओं तथा मुसलमानों के नाम, आबादी में उनके अनुपात की तुलना में उल्लेखनीय रूप से ज्यादा थे। यानी यह अपनी संरचना से ही, कमजोर तबकों के मताधिकार छीनने का हथियार है।बहरहाल, दूसरे चरण में और खासतौर पर बंगाल में, एसआईआर को चुनाव की ओर सीधे-सीधे प्रभावित करने के हथियार में तब्दील कर दिया गया। चूंकि इस राज्य में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी की विरोधी पार्टी सत्ता में थी, संभावित विपक्षी मतदाताओं पर सामान्य रूप से बड़े पैमाने पर कैंची चलाना मुश्किल था। इसलिए, एसआईआर के पहले चरण के बाद, चुनाव आयोग ने समूची प्रक्रिया को बाहर से लाए गए केंद्रीय शासन के कप्तानर अधिकारियों के हाथों में सौंपने के अलावा एक ऐसे अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापार का ढांचा लगभग तैयार है। लेकिन भारत-अमेरिका व्यापार बातचीत के आखिरी दौर में भी, अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत प्रतिबंध लगाने की बात कही। इसका मतलब था कि जांच के दायरे में आने वाले देशों (जिनमें भारत भी शामिल है) पर 12.5 प्रतिशत ड्यूटी लगाई जाएगी।

प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी लैंडाऊ के बयान का लहजा कई व्यापार विशेषज्ञों की उन आशंकाओं को सही ठहराता है कि अमेरिका के हितों की रक्षा हो रही है, भारत के हितों की रक्षा हो रही है।

जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई, जन समाधान दिवस में 10 शिकायतें निस्तारित

अरुण कुमार रवि

झारखण्ड: नगर पंचायत छतरपुर द्वारा बुधवार को नगर पंचायत सभागार में आयोजित जन समाधान दिवस आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी मंच साबित हुआ। कार्यक्रम में नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को लेकर पहुंचे। नगर पंचायत प्रशासन ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया, जबकि शेष मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जन समाधान दिवस के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, होलिंग टैक्स, सड़क एवं नाली निर्माण, साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जल निकासी, अतिक्रमण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, वार्डों में विकास कार्यों की प्रगति सहित विभिन्न जनसुविधाओं से जुड़ी 20 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 10 से अधिक शिकायतों का समाधान अधिकारियों ने मौके पर ही कर दिया। जिन मामलों में तकनीकी या विभागीय प्रक्रिया आवश्यक थी, उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।



कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष अरविन्द गुप्ता 'चुन्मत्' ने कहा कि नगर पंचायत का मूल उद्देश्य जनता को पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन तभी सफल माने जाएंगे जब आम नागरिक बिना किसी परेशानी के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत कार्यालय जनता की सेवा के लिए है और किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए प्रशासन लगातार व्यवस्था को और बेहतर बना रहा है। जन

समाधान दिवस इसी सोच का परिणाम है, जहां एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं की सुनवाई और समाधान की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष मंजीत यादव ने कहा कि जन समाधान दिवस नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत प्रत्येक वार्ड में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को छिपाने के बजाय सीधे प्रशासन के समक्ष रखें, ताकि उनका शीघ्र समाधान किया जा सके। कायापालक पदाधिकारी फैजुर रहमान ने कहा

कि नगर पंचायत नागरिकों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्राप्त सभी शिकायतों का डिजिटल एवं विभागीय स्तर पर पंजीकरण किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। जिन शिकायतों का तत्काल समाधान संभव नहीं है, उनके लिए संबंधित शाखाओं को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने से नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है। एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई और समाधान की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इससे लोगों का समय, श्रम और धन तीनों की बचत हो रही है तथा प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बन रही है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने बारी-बारी से लोगों की समस्याएं सुनीं और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया। जिन मामलों में स्थल निरीक्षण या अन्य विभागों से समन्वय आवश्यक था, उन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जन समाधान दिवस में पहुंचे नागरिकों ने नगर पंचायत की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पहले छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही मंच पर अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में समस्याओं का समाधान हो रहा है। इससे आम लोगों का समय बच रहा है और प्रशासन के प्रति विश्वास भी लगातार बढ़ रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में भी जन समाधान दिवस का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा ताकि प्रत्येक नागरिक को उसकी समस्या का समयबद्ध समाधान मिल सके। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का लक्ष्य छतरपुर को स्वच्छ, सुंदर, विकसित, पारदर्शी और जनहितैषी नगर बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों और प्रशासन जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह रहे। इस अवसर पर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मंजीत यादव, कायापालक पदाधिकारी फैजुर रहमान, सिटी मैनेजर मुर्तजा अंसारी, सभी वार्ड पार्षद, नगर पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन नागरिकों को उनकी शिकायतों के शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाते हुए किया गया।



प्रमोद कुमार बंसल

राजस्थान: कोटपूतली जिले के मोलाहेड़ा क्षेत्र में वाहन में आग लगने की काल्पनिक घटना पर आधारित जिला प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग और चिकित्सा विभाग द्वारा संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया और राहत-बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल में परिकल्पना की गई कि यात्रियों से भरी बस गैस टैंकर से टकराने के बाद बिजली के पोल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसमें लगभग 10 लोग घायल हो जाते हैं। घायलों में मुकेश (22), कार्तिक (23), विशाल सिंह (22), अनिल कुमार (27), शशांक तिवाड़ी (24), विकास (23), धर्मेन्द्र (29), सुनील (30), राहुल (22) और आनंद

(21) शामिल बताए गए। राहत की बात यह रही कि यह पूरी घटना काल्पनिक थी और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और मानक संचालन प्रक्रिया (रड्ड) के अनुसार राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

इस दौरान आग पर नियंत्रण, क्षेत्र की घेराबंदी, यातायात प्रबंधन, फंसे हुए लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू, प्राथमिक उपचार तथा घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान विभागों की त्वरित कार्रवाई क्षमता, मेडिकल टीम की तत्परता, रिसर्पॉन्स टाइम और आपसी समन्वय का भी परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने इस अभ्यास को वास्तविक आपदा प्रबंधन तैयारियों को मजबूत करने

की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और जिला पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल से आपदा प्रबंधन प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होती है तथा विभागों की कार्यक्षमता का आकलन संभव होता है।

उन्होंने सभी विभागों को आपात परिस्थितियों के लिए संसाधनों को हमेशा तैयार रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़क दुर्घटना या आग लगने की स्थिति में तुरंत सुरक्षा घेरा बनाना, भीड़ को नियंत्रित करना और समय पर संबंधित विभागों को सूचना देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने वाहन चालकों से नियमित तकनीकी जांच कराने और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की अपील की।

ग्रामीणों ने जर्जर सड़कों की मरम्मत को लेकर जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन



प्रमोद कुमार बंसल

राजस्थान: कोटपूतली ग्राम सुंदरपुरा दाढ़ा के ग्रामीणों ने गांव की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण की मांग को लेकर उप मुख्यमंत्री दीपा कुमारी के नाम जिला कलक्टर अपर्णा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि सुंदरपुरा से मीरापुर फॉर्म तक जाने वाली लगभग 2 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। सड़क पर 2-2 फीट गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। यह सड़क

ग्रामीणों को मुख्य कस्बे से जोड़ने का एकमात्र साधन है। ग्रामीणों ने कहा कि बारिश के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है। जलभराव और कीचड़ के कारण आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और वे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा सुंदरपुरा से दाढ़ा की ओर चंदा मोड़ से इंद्राज टंकी तक लगभग 400 मीटर का रास्ता भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग भी बेहद खराब हालत में है, जिससे आवागमन बाधित है। इस दौरान सरपंच उमेश यादव सहित बड़ी

प्रकाश गडरी

राजस्थान: राजस्थान के कपासन और राशमी क्षेत्र में बनास नदी में कथित अवैध बजरी खनन को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। वर्षा ऋतु के दौरान खनन पर प्रतिबंध होने के बावजूद नदी क्षेत्र में बजरी खनन जारी रहने के आरोपों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर खनन गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जबकि जिम्मेदार विभाग इस पर प्रभावी कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि बरसात के मौसम में नदी से बजरी निकालने पर रोक के स्पष्ट नियम होने के बावजूद खनन माफिया बेखौफ होकर सक्रिय हैं। उनका कहना है कि इस अवैध गतिविधि से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि नदी के प्राकृतिक स्वरूप और आसपास



के क्षेत्रों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय और भौगोलिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि आखिर प्रतिबंध के बावजूद बनास नदी में बजरी खनन किसके संरक्षण में चल रहा है। यदि खनन

अवैध है तो संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। लोगों ने यह भी पूछा कि अवैध खनन पर पूरी तरह रोक कब लगेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कब होगी। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी और जनप्रतिनिधियों की खामोशी से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद

स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इससे यह धारणा बन रही है कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नहीं है।

जनता ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि कहीं भी अवैध बजरी खनन हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से उसे बंद कराया जाए। साथ ही अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। स्थानीय लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि संबंधित विभाग मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करेगा और यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे तत्काल रोका जाएगा।

गाय को चारा देने गए पशुपालक पर शेर का हमला ग्रामीणों ने बचाई जान वीडियो हुआ वायरल

प्रकाश गडरी

गुजरात: भावनगर जिले के पालिताना क्षेत्र के गरजिया गांव में एक पशुपालक पर शेर के हमले की घटना सामने आई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है,



जिसमें शेर पशुपालक का हाथ अपने जबड़ों में दबाए हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल पशुपालक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, गरजिया गांव निवासी पशुपालक **कालुभाई परमार** रोज की तरह सुबह अपने पशुओं को चारा देने के लिए गए थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपा एक शेर

अचानक उनके सामने आ गया और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से कालुभाई संभल नहीं सके और शेर ने उनका हाथ अपने जबड़ों में दबा लिया। पशुपालक के शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर

पहुंचे और हिम्मत दिखाते हुए शेर को भगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों के शोर-शराबे के बाद शेर वहां से जंगल की ओर भाग गया, जिससे कालुभाई की जान बच सकी। घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने घायल पशुपालक को प्राथमिक उपचार के बाद भावनगर के अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने बताया कि उनके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति अब

खतरे से बाहर है। अस्पताल में उनका उपचार जारी है और डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य पर निगरानी रखे हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

वन विभाग के अनुसार, यह क्षेत्र वन्यजीवों की आवाजाही वाला इलाका है और यहां अक्सर शेरों की मौजूदगी देखी जाती है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई है कि किसी कारणवश शेर उग्र हो गया, जिसके बाद उसने हमला किया। हालांकि हमले के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही की जाएगी। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल या वन क्षेत्र से सटे इलाकों में जाते समय विशेष सावधानी बरतें और यदि आसपास किसी वन्यजीव की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत विभाग को सूचना दें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है तथा वन विभाग की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

गलाघोंटू बीमारी से बचाव के लिए पशुपालन विभाग ने शुरू किया विशेष टीकाकरण अभियान, घर-घर पहुंची टीम



अंकित कुमार

उत्तर प्रदेश: गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील क्षेत्र में पशुओं को घातक संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान चलाया। सोमवार को रायपुर गांव में विभाग की टीम ने घर-घर पहुंचकर गाय, भैंस और बछड़ों का गलाघोंटू (हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया) रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया। बदलते मौसम और वर्षा ऋतु को देखते हुए विभाग ने पशुपालकों से समय पर टीकाकरण कराने की अपील की। पशु चिकित्साधिकारी के निर्देशन में मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी एवं उनकी टीम ने गांव का दौरा कर पशुपालकों के घरों पर बंधे मवेशियों को टीके लगाए। इस

दौरान पशुपालकों को गलाघोंटू बीमारी के प्रति जागरूक भी किया गया और इसके लक्षणों एवं बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। टीम ने बताया कि गलाघोंटू एक अत्यंत संक्रामक एवं जानलेवा जीवाणु जनित बीमारी है, जिसका खतरा वर्षा ऋतु की शुरूआत में सबसे अधिक रहता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में अचानक तेज बुखार आना, गले में सूजन होना, सांस लेने में परेशानी या घुर-घुर की आवाज आना तथा मुंह से अत्यधिक लार टपकना शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय समय पर टीकाकरण कराना है। पशुपालन विभाग ने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने सभी मवेशियों का समय पर टीकाकरण कराएं, किसी भी पशु को

टीकाकरण से वंचित न रहें तथा बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। साथ ही बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखने की भी सलाह दी गई, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। रायपुर गांव के ग्रामीणों और पशुपालकों ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे डोर-टू-डोर टीकाकरण अभियान की सराहना की और टीम का सहयोग करते हुए अपने मवेशियों का टीकाकरण कराया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तहसील क्षेत्र के अन्य गांवों में भी चरणबद्ध तरीके से शत-प्रतिशत पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा, ताकि संभावित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके और पशुधन को सुरक्षित बनाया जा सके।

एक नजर

पीला जोहड़ की सफाई के बाद मृत मछलियों के निस्तारण की उठी मांग



प्रमोद कुमार बंसल/राजस्थान: कोटपूतली निकटवर्ती ग्राम सांगटेड़ा स्थित जन-आस्था के केंद्र पीला जोहड़ में सैकड़ों मछलियों की मौत के बाद शुरू हुआ सफाई अभियान अब पूरा हो गया है, लेकिन मृत मछलियों के खुले में फेंके जाने से नई समस्या खड़ी हो गई है। इससे क्षेत्र में बदबू और संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष तारा पूतली ने पहले जोहड़ में मछलियों की मौत का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद नगर परिषद ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सफाई अभियान शुरू किया। सफाई कर्मचारियों ने जाल की मदद से जोहड़ से मृत मछलियों को बाहर निकाला। हालांकि, सफाई के दौरान निकाली गई मछलियों का उचित निस्तारण नहीं किए जाने पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि मृत मछलियों को खुले में ही फेंक दिया गया, जिससे दुर्गंध और संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है।

तारा पूतली ने मौके पर निरीक्षण के दौरान कहा कि सफाई केवल कचरा हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण भी जरूरी है। उन्होंने नगर परिषद से मांग की कि मृत मछलियों को गांव से दूर गहरे गड्ढे में दबाया जाए या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल सफाई का नहीं बल्कि जन-स्वास्थ्य, पर्यावरण और आस्था से जुड़ा है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि नगर परिषद इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत ध्यान देगी। फिलहाल जोहड़ की सफाई तो कर दी गई है, लेकिन उचित निस्तारण की मांग अब प्रमुख मुद्दा बनी हुई है।

एनएचआई ने शुरू की हाईवे की राइट ऑफ वे सीमा की मार्किंग, अतिक्रमण हटाने की तैयारी हुई तेज



प्रमोद कुमार बंसल/राजस्थान: कोटपूतली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने कोटपूतली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग की राइट ऑफ वे (Right of Way) सीमा की मार्किंग का कार्य शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत हाईवे किनारे स्थित स्थायी और अस्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित किया जा रहा है, जिससे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। एनएचआई अधिकारियों के अनुसार दुकानों के आगे बने बचतूरे, बाउंड्री वॉल, रैप, सीढ़ियां और अन्य अवैध निर्माणों पर निशान लगाए जा रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2009-11 के दौरान राइट ऑफ वे के अंतर्गत आने वाली भूमि का मुआवजा संबंधित भूमि स्वामियों को दिया जा चुका है। सर्वेचक न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के समन्वय से हाईवे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन ने हाईवे किनारे रहने वाले लोगों और व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित सीमा में आने वाले अतिक्रमण स्वयं हटा लें, ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। इस अभियान का उद्देश्य राजमार्ग की सुरक्षा बढ़ाना, यातायात को सुगम बनाना और सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना बताया गया है।

समाजसेवा और जनहित के लिए सक्रिय परसोतमभाई मुंगरा, किसानों की आवाज बने

संजित्रा आशाबेन

गुजरात: राजकोट के एसपीजी श्री सरदार पटेल सेवादल के सदस्य तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े समाजसेवी एवं न्याय एवं अधिकार समिति, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री परसोतमभाई नाथाभाई मुंगरा पटेल समाजसेवा और जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे विभिन्न समितियों एवं संगठनों के माध्यम से निडर होकर जनता और गुजरात के किसानों की आवाज उठाते हैं। उनका कहना है कि यदि पाटीदार समाज के साथ कहीं भी अन्याय होता है, तो वे उसके खिलाफ भी पूरी निडरता से संघर्ष करेंगे। वे पुलिस मित्र संगठन से भी जुड़े हुए हैं और राजकोट जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही वे भारत निविदा लाइन समाचार में राजकोट जिला क्राइम रिपोर्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं।

श्री मुंगरा भ्रष्टाचार के खिलाफ



आवाज बुलंद करते हैं तथा गुजरात में शराब, जुआ, गांजा, चरस, लूट, हत्या, गुंडागर्दी, असामाजिक तत्वों और जनता को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते हैं। वे किसानों के साथ हार्डिशन बिजली लाइन के मुद्दे पर हो रहे अन्याय के खिलाफ भी मजबूती से आवाज उठाते हैं। इसके अलावा, बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का उचित मुआवजा मिले, इसके लिए भी वे लगातार किसानों के साथ खड़े रहते हैं।

शहरी क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, सफाई, सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट, भूमिगत सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी वे संबंधित सरकारी विभागों के समक्ष लगातार आवाज उठाते हैं। हाईवे अथवा शहर में सड़क दुर्घटना होने पर वे तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना देकर घायलों को समय पर सहायता पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यदि कहीं सड़क पर गड़्डे हो जाते हैं तो उनके मरम्मत के लिए भी संबंधित विभाग को अवगत

कराते हैं।

वे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के साथ-साथ घायल पशु-पक्षियों के उपचार के लिए भी हर संभव सहयोग करते हैं। वर्तमान में वे एसपीजी श्री सरदार पटेल सेवादल से जुड़े हुए हैं। उनका उद्देश्य पाटीदार समाज के संगठन को मजबूत बनाना तथा समाज के गरीब, जरूरतमंद और असहाय लोगों की सहायता करना है। उनका मानना है कि समाज के लिए उपयोगी कार्य करने हेतु अधिक से अधिक लोगों को इस संगठन से जुड़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि श्री सरदार पटेल सेवादल मेहसाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजीभाई पटेल पाटीदार समाज के प्रति गहरा प्रेम और समर्पण रखते हैं। वे नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित कर जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। इस संगठन से जुड़कर अनेक लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में

पाटीदार समाज के लिए संकट की

घड़ी में इस प्रकार सहयोग करने वाली संस्थाएं बहुत कम हैं। यह संस्था वास्तव में निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा समान है। उन्होंने पाटीदार समाज से अपील करते हुए कहा कि वे स्वयं, अपने परिवार तथा अपने रिश्तेदारों को भी एसपीजी श्री सरदार पटेल सेवादल का सदस्य बनाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संगठन की सहायता प्राप्त हो सके। एसपीजी की आजीवन सदस्यता शुल्क मात्र 1200 है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी इस संगठन के आजीवन सदस्य हैं। अंत में न्याय एवं अधिकार समिति, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष श्री परसोतमभाई एन. मुंगरा ने सभी से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजीभाई पटेल मेहसाणा के नेतृत्व में श्री सरदार पटेल सेवादल (SPG) से जुड़कर पाटीदार समाज की सेवा करें और समाज को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।

खेत के कुएं में मिला वयस्क नर भालू का क्षत-विक्षत शव, शिकार की आशंका से मची सनसनी

अशोक महूले

मध्य प्रदेश: जिले के वन परिक्षेत्र खैरलांजी सर्किल अंतर्गत ग्राम भंडारबोड़ी के पिपरटोला में उस समय सनसनी फैल गई जब खेत के कुएं से एक वयस्क नर भालू का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में वन विभाग ने शिकार की आशंका जताई है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह किसान जियालाल धुर्वे अपने खेत पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने खेत में बने कुएं में किसी मृत जीव के अवशेष देखे और तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी डी.सी. वासनिद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान पाया गया कि कुएं में पड़े अवशेष एक वयस्क नर भालू के हैं। हैरान करने वाली बात यह रही कि भालू के शरीर के कई टुकड़े कर उसे कुएं में फेंका गया था। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारी एसडीओ, डीएफओ एवं सीसीएफ को भी अवगत कराया गया,



जिसके बाद डॉग स्कॉड टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए।

वन विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि भालू का सिर धड़ से अलग था, चारों पैर काट दिए गए थे तथा आगे के दोनों पैरों के नाखून भी गायब थे। शव लगभग छह से सात हिस्सों में मिला, जिससे आशंका जताई जा रही है कि शिकार के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। अधिकारियों के अनुसार शव दो से तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद पशु चिकित्सकों

द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया और नियमानुसार वन्यजीव का अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस गंभीर मामले में दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है।

प्रांतीय जोनल कमेटी के को-कन्वीनर बने उमापति पांडेय, अधिवक्ताओं ने किया सम्मानित

इंद्रेश कुमार पांडे

उत्तर प्रदेश: सोनभद्र में दी सोनभद्र टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उमापति पांडेय को उत्तर प्रदेश क्रूर अधिवक्ता संगठन पंजीकृत, लखनऊ उपकास की 67वीं प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक, जो विगत दिनों आजमगढ़ में आयोजित हुई थी, में उपकास के प्रांतीय अध्यक्ष आर. पी. यादव द्वारा प्रांतीय जोनल कमेटी का को-कन्वीनर मनोनीत किए जाने पर आज दी सोनभद्र टैक्स बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा नगर के एक होटल में उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर बार के पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने श्री पांडेय को पुष्पमालाओं एवं अंगवस्त्र से सम्मानित करते हुए उन्हें नई



जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। वक्ताओं ने कहा कि श्री उमापति पांडेय का दीर्घकालीन अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण तथा अधिवक्ताओं के हितों के लिए उनका निरंतर योगदान उपकास की और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाएगा।

अपने सम्मान से अभिभूत श्री उमापति पांडेय ने उपकास के प्रांतीय नेतृत्व, विशेष रूप से प्रांतीय अध्यक्ष श्री आर. पी. यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्व का वे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे तथा प्रदेश भर

के कर अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा एवं संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदैव सक्रिय रहेंगे। कार्यक्रम का वातावरण आत्मीय एवं उत्साहपूर्ण रहा तथा उपस्थित सभी अधिवक्ताओं ने श्री पांडेय के उज्ज्वल कार्यकाल की कामना करते हुए उन्हें पुन शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस अवसर पर उपकास के प्रांतीय महामंत्री राकेश शरण मिश्र दी सोनभद्र टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश देव पाण्डेय, उपाध्यक्ष सुरेंद्र केशरी, महामंत्री फैजान अंसारी, सहसचिव प्रदीप धर द्विवेदी वी के रावत, प्रवक्ता राकेश पति तिवारी रमेश केशरी,जनादन पांडेय प्रसिद्ध नाथ सोनी,चेयरमैन एल्डर कमेटी कृष्णाकांत तिवारी, सदस्य एण्डर कमेटी अधिवक्ता सतीश पांडेय मुख्य रूप से उपस्थित थे।

माहेश्वरी कांजीभाई नारणभाई

गुजरात: कच्छ मुंद्रा तहसील के शिराचा क्षेत्र में स्थित कच्छ कॉपर कंपनी के मुख्य गेट के बाहर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक विद्युत ट्रांसफॉर्मर में अचानक जोरदार धमाका होने के बाद भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रांसफॉर्मर के पास खड़ी कई मोटरसाइकिलों को अपनी चोपट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रांसफॉर्मर से पहले तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ, जिसके बाद उसमें से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रांसफॉर्मर के आसपास पार्क की गई कई बाइकें जलकर पूरी तरह खाक हो गईं। घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई।

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद



आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जहानिया गंभीर चोट की कोई सूचना सामने नहीं आई है। हालांकि, आग के कारण भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है।

जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार भारी पुलिस सुरक्षा में, बेटे ने जेल प्रशासन पर हत्या के आरोप लगाए



सांवर माल गदारी

राजस्थान: धौलपुर जिले में जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार शुक्रवार को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। पूरे क्षेत्र में किसी भी अग्रिय स्थिति से बचने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अंतिम संस्कार के दौरान मुक्त के परिजनों और रिश्तेदारों को पुलिस सुरक्षा में मौके पर लाया गया। इस दौरान उनके भाई लाल सिंह, पान सिंह और पप्पू भी मौजूद रहे। अंतिम संस्कार की सभी रस्में पुलिस निगरानी में पूरी कराई गईं ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

सबसे अहम घटना तब सामने आई जब मुक्त के बेटे आशाराम ने अपने पिता को मुखाम्ति दी। अंतिम संस्कार के बाद आशाराम ने मोडिया और मौजूद लोगों के सामने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जेल प्रशासन पर उनके पिता की साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आशाराम ने कहा कि परिवार की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनके आरोपों के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा।

अधिवक्ता पर हमले के विरोध में तकीलों का तहसील तक प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग हुई तेज

देवेश यादव

उत्तर प्रदेश: महोबा जनपद महोबा में साथी अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना के विरोध में जिला अधिवक्ता समिति के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर से तहसील तक पैदल विरोध मार्च निकालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि एक साथी अधिवक्ता पर जानलेवा हमला अत्यंत निंदनीय एवं गंभीर घटना है, लेकिन इसके बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि घटना के बाद से ही वे न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अधिवक्ता समुदाय में गहरा असंतोष और रोष व्याप्त है।



अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो वे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि न्याय व्यवस्था की रक्षा के लिए अधिवक्ता समुदाय सदैव अग्रिम पंक्ति में रहता है, ऐसे में अधिवक्ताओं पर हमले किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जा सकते। जिला अधिवक्ता समिति के

पदाधिकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुलिस-प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विरोध मार्च के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे और कचहरी से तहसील तक पैदल मार्च करते हुए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पूरे मार्ग में अधिवक्ताओं ने

शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराया, लेकिन माहौल में गहरा आक्रोश स्पष्ट दिखाई दिया। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि अधिवक्ता समाज पर हमला न्याय व्यवस्था पर हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में अधिवक्ता समिति ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग दोहराई और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने शुरु किया वृक्षारोपण अभियान, पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए ट्री गार्ड



सहीदुरहमान

राजस्थान: टोंक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान के तहत मंगलवार को टोंक जिला मुख्यालय के बाहरी क्षेत्र में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान का संचालन मंच के संरक्षक डॉ. ईश कुमार के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। राजस्थान प्रभारी एवं राष्ट्रीय संयोजक अबू बकर नकवी के निदेश पर प्रदेशभर के जिलों और ब्लॉक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वृक्षारोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पौधे के चारों ओर लोहे के ट्री गार्ड लगाए गए। मंच पदाधिकारियों ने बताया कि पौधों

को पशुओं और अन्य नुकसान से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है, ताकि भविष्य में ये पेड़ बड़े होकर राहगीरों को छाया तथा पक्षियों और अन्य जीव-जंतुओं को आश्रय प्रदान कर सकें। इस अवसर पर अजमेर संभाग के सह-संयोजक अशरफ कलंदर, जिला संयोजक शकील अहमद, सह-संयोजक ईद मोहम्मद पंजाबी, जुनैद अहमद, अब्दुल वहीद, मोहम्मद हसीन, आबिद अली, इस्लाम मोहम्मद, अब्दुल लतीफ नकवी, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद सिद्दीकी सहित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी निर्यात देखभाल करने का आह्वान भी किया गया।

हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से घुसे ट्रक से दो युवक गंभीर घायल

अभव

उत्तर प्रदेश: शाहजहांपुर लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्वी भक्सी तिराहे के पास गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने डेल से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रैक्टर चालक रिकू (निवासी बिहारीपुर) और रोहित (निवासी मित्रपुर बरूआ) ट्रॉली के नीचे दब गए और गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तत्परा दिखाते हुए दोनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया। प्राथमिक



उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के चलते हाईवे पर करीब 30 मिनट

तक यातायात बाधित रहा, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को सुचारु

कराया। सीओ इश्का सिंह ने बताया कि ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हादसे के बाद क्षेत्र में एक बार फिर पूर्वी भक्सी तिराहे पर प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण की मांग तेज हो गई। कांग्रेस नेता जाने आलम ने प्रशासन से तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग करते हुए कहा कि स्वीकृत के बावजूद कार्य शुरू नहीं होने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इसी स्थान पर एक युवक की जान जा चुकी है।

साइबर फ्रॉड के शिकार पीड़ित को मिली राहत, पुलिस ने लौटाए 1.51 लाख रुपये

राकेश कुमार शर्मा

उत्तर प्रदेश: सहारनपुर जनपद सहारनपुर की थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीम ने ऑनलाइन साइबर ठगी के एक मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के खाते में ठगी गई 1,51,507 रुपये की धनराशि वापस कराकर बड़ी सफलता हासिल की है। पीड़ित ने धनराशि वापस मिलने पर सहारनपुर पुलिस और साइबर हेल्पडेस्क टीम का आभार व्यक्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 फरवरी 2026 को रोहित विहार कॉलोनी, हसनपुर चुर्गी निवासी नरेश कुमार पुत्र धारा सिंह ने थाना सदर बाजार पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ने वीडियो कॉल के माध्यम से फ्रॉड कांड संबंधी जानकारी हासिल कर ऑनलाइन साइबर फ्रॉड करते हुए उनके खाते



से कुल 1,51,507 रुपये की रकम ठग ली। इस संबंध में थाना सदर बाजार साइबर हेल्पडेस्क पर शिकायत संख्या 33102260037499 दर्ज की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में चलाए जा रहे साइबर अपराध रोकथाम अभियान के तहत पुलिस

अधीक्षक नगर एवं नोडल अधिकारी साइबर क्राइम, क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के पथविशेष तथा प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसेन सेनी के नेतृत्व में साइबर हेल्पडेस्क टीम ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने तकनीकी जांच और संबंधित बैंकिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से साइबर ठगी की गई पूरी धनराशि को होल्ड करवाकर पीड़ित के खाते में वापस कराया। पुलिस की सक्रियता के चलते पीड़ित को उसकी पूरी रकम वापस मिल गई। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक चन्द्रसेन सेनी, निरीक्षक आनंद पोसवाल, उपनिरीक्षक सुरेन्द्र शर्मा तथा कंप्यूटर ऑपरेटर गौरव मटान की विशेष भूमिका रही। सहारनपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ बैंक खाते, ओटीपी, क्रेडिट कार्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें।



सामंथा की 'मां इंटी बंगारम' का बनेगा सीक्वल

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'मां इंटी बंगारम' का सीक्वल बनने वाला है। इस बात की पुष्टि खुद फिल्म के राइटर राज निदिमोरु ने की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।

'मां इंटी बंगारम' की जबरदस्त सफलता के बाद विजाग में एक रैंड सक्सेस मीट रखा गया था। इसी दौरान राज निदिमोरु ने फैंस को सरप्राइज देते हुए बताया कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी आएगा। राज ने पहले वहां मौजूद लोगों से पूछा कि क्या वे इस कहानी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। जैसे ही लोगों ने जोरदार तालियां और चीयर किया, उन्होंने सीक्वल की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, 'मेरे दिमाग में पहले से एक आइडिया है। वही टीम इस पर काम करेगी। पहली बार मुझे किसी फिल्म का दूसरा पार्ट बनाने की प्रेरणा मिली है। इसमें दोगुना मजा और दोगुना एक्साइटमेंट होगा। आगे चलकर मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा।' राज ने यह भी बताया कि 'मां इंटी बंगारम' को लोगों से इतना प्यार मिला कि उन्हें अपने पुराने हिट प्रोजेक्ट्स से भी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि यह फिल्म सीधे दिल को छू गई। नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सामंथा रूथ प्रभु के साथ गुलशन देवैया, श्रीमुखी और दिगंत मंचले नजर आए। इस फिल्म को सामंथा, राज निदिमोरु और हिमांशु ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो यह फिल्म महिला लीड पर आधारित फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

1980 के दौर पर आधारित इस कहानी में सामंथा 'स्वर्णा' का किरदार निभा रही हैं, जो अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ एक डॉक्टर से शादी करती है। शुरुआत में उसे ससुराल वालों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन धीरे-धीरे वह सबका दिल जीत लेती है। तभी उसका अतीत लौटकर उसकी जिंदगी में उथल-पुथल मचा देता है।



सनी देओल के साथ काम करना मेरे करियर के लिए सौभाग्य की बात

अभिनेत्री दीपा मिर्जा ने अभिनेता सनी देओल के साथ काम करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभिनेता के साथ काम करना, उनके करियर के लिए सौभाग्य की बात है। फिल्म 'इक्का' में दीपा मिर्जा और सनी देओल साथ दिखाई देंगे। 'इक्का' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बात करते हुए दीपा ने कहा कि वह हमेशा से देओल परिवार की प्रशंसक रही हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हां कहने की वजह बताते हुए दीपा ने कहा, 'जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे यह बहुत दिलचस्प, मानवीय और दमदार लगी। इसमें किरदारों को बहुत अनाखे, दिलचस्प और आकर्षक ढंग से दिखाया गया है, इसलिए मुझे हां कहना ही पड़ा। सनी देओल के साथ काम करना मेरे करियर के लिए सौभाग्य की बात है और मैं इसे लेकर बहुत खुश थी।' उन्होंने अपने को-स्टार्स तिलोत्तमा शोम और अक्षय खन्ना की भी तारीफ की।

दीपा मिर्जा ने कहा कि मैं हमेशा से देओल परिवार की दयालुता, उदारता और जमीन से जुड़े रहने की तारीफ करती रही हूं। सनी

देओल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा मैंने सोचा था, बल्कि उससे भी बेहतर। मैंने टीजर लॉन्च के समय भी यह बात कही थी। ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना जिसमें तिलोत्तमा शोम और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार हों, यह सच में अद्भुत है और सिद्धार्थ ने कहानी को बहुत संवेदनशीलता और समझदारी से पेश किया है। दीपा मिर्जा ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा कि अवतिका एक ऐसी महिला है जो अपने आसपास के लोगों को अपनापन, हिम्मत और स्थिरता देती है, तब भी जब जिंदगी बहुत अनिश्चित हो जाती है। मैं उसकी हिम्मत और उस शांत साहस से प्रभावित हुई जिसके साथ वह अपनी चुनौतियों का सामना करती है। उन्होंने कहा कि 'इक्का' की खासियत यह है कि कोर्टरूम ड्रामा के पीछे परिवार, प्यार और मुश्किल फैसलों की एक गहरी मानवीय कहानी है। मैं नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी कहानी के साथ वापसी करके बहुत खुश हूं जो भावनात्मक रूप से समृद्ध और बहुत दिलचस्प है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे जरूर देखेंगे।

फिल्म 'मारिया' को जल्दबाजी में रिलीज करने के पक्ष में नहीं हैं रोहित शेट्टी



जॉन अब्राहम-तमन्ना भाटिया स्टारर प्रोजेक्ट 'मारिया' लगभग तैयार हो गया है। निर्देशक रोहित शेट्टी निर्देशित इस फिल्म में राकेश मारिया की जिंदगी और मुंबई

अंडरवर्ल्ड की असली जंग पर आधारित कहानी देखने को मिलेगी। हालांकि दर्शकों को इसकी रिलीज के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आमतौर पर किसी फिल्म की 95 फीसदी शूटिंग पूरी हो जाए तो मेकर्स रिलीज डेट

तलाशने लगते हैं लेकिन रोहित की इस महत्वाकांक्षी फिल्म 'मारिया' की स्थिति इसके ठीक उलट है। यह प्रोजेक्ट लगभग तैयार माना जा रहा है, बावजूद इसके इसकी बची हुई शूटिंग और रिलीज दोनों फिलहाल थमी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि रोहित का पूरा ध्यान इस समय अपनी कॉमेडी फ्रेंचाइज गोलमाल पर है।

एसेल स्टूडियो से हुई थी शुरुआत, कुछ पैचवर्क का काम है बाकी सूत्रों के अनुसार फिल्म की मुख्य शूटिंग तो काफी पहले पूरी हो चुकी है पर अभी कुछ पैचवर्क, क्लोज-अप शॉट्स और सीमित सीक्वेंस ही बाकी हैं। तकनीकी तौर पर प्रोजेक्ट लगभग तैयार है लेकिन मेकर्स जल्दबाजी में इसे रिलीज करने के पक्ष में नहीं हैं। फिल्म की शुरुआत मुंबई के ट्रॉम्बे स्थित एसेल स्टूडियो से हुई थी, जहां पुलिस मुख्यालय, जांच कक्ष और प्रशासनिक दफ्तरों के बड़े सेट तैयार किए गए थे।



बॉलीवुड बनाम रीजनल सिनेमा की तुलना पर बोलीं दिव्या दत्ता

आज के दौर में बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा की तुलना करते लोग हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। इस पर अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अपने विचार रखे हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री को एक ही नजरिए से देखना सही नहीं है। हर जगह अच्छी और खराब दोनों तरह की फिल्में बनती हैं। असली फर्क भाषा का नहीं, बल्कि कहानी और प्रस्तुति का होता है। जब दिव्या दत्ता से पूछा कि क्या रीजनल सिनेमा कॉमेडी फिल्मों को बॉलीवुड से बेहतर तरीके से पेश कर रहा है, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा, 'इस तरह की तुलना करना सही नहीं है। किसी भी कॉमेडी फिल्म की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कहानी कितनी मजबूत है और उसे दर्शकों के सामने किस तरह पेश किया

गया है। मेरा मानना है कि अगर कंटेंट अच्छा है, तो वह किसी भी भाषा में हो, दर्शकों को जरूर पसंद आता है।' दिव्या दत्ता ने कहा, 'फिल्म इंडस्ट्री को भाषा के आधार पर बांटना ठीक नहीं है। चाहे फिल्म हिंदी में हो, किसी रीजनल भाषा में हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी हो, अगर कहानी दमदार है और उसे सही तरीके से दिखाया गया है तो वह लोगों के दिलों तक पहुंचती है। आज दर्शक काफी समझदार हो चुके हैं और वे सिर्फ नाम या भाषा देखकर फिल्म को पसंद नहीं करते, बल्कि कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं।'



सेफ हैंड में है मेरा हिंदी डेब्यू अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म के संगीत को लेकर उत्साहित हैं जीवी प्रकाश

तमिल और तेलुगु सिनेमा में एक म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद जीवी प्रकाश कुमार अब 'नई नवेली' के साथ अपनी पहली बड़ी हिंदी फिल्म का म्यूजिक देने के लिए तैयार हैं। यह प्रोजेक्ट आनंद एल राय के प्रोडक्शन हाउस का है और इसे बालाजी मोहन डायरेक्ट कर रहे हैं। म्यूजिशियन जो एआर रहमान के भतीजे भी हैं ने यामी गौतम घर की फिल्म के लिए म्यूजिक बनाने, लिप-सिंक गानों के सदाबहार आकर्षण और अपनी फीस को लेकर उड़ रही अफवाहों के बारे में बात की।

अपने डेब्यू को बताया दिलचस्प 'नई नवेली' के लिए अपना पहला पूरा हिंदी म्यूजिक स्कोर तैयार करने के बारे में 'वेरायटी इंडिया' से बात करते हुए जीवी प्रकाश कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपने सफर को याद किया। प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' पर काम करने का मौका मिला, क्योंकि अनुराग कश्यप मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन यह मेरे लिए पूरी तरह से हिंदी डेब्यू नहीं था। जहां तक आनंद एल राय के बैनर तले बन रही 'नई नवेली' की बात है, तो मैं इसके सभी गाने कंजोज कर रहा हूं। यह बहुत दिलचस्प होगा। मुझे यकीन है कि गाने बहुत अच्छे बनेंगे। यामी गौतम इसमें लीड रोल निभा रही हैं। हम सब जानते हैं कि वह कितनी खूबसूरती से भावनाएं

जाहिर करती हैं। इसलिए मेरे गाने सुरक्षित हाथों में हैं। 'नई नवेली', जिसे बालाजी मोहन डायरेक्ट कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म होगी जिसका बेसबी से इंतजार रहेगा।

हर म्यूजिक स्कोर मेरे लिए एक चुनौती है

जब उनसे पूछा गया कि क्या हिंदी फिल्म के लिए म्यूजिक बनाना तमिल या तेलुगु प्रोजेक्ट पर काम करने से अलग लगता है? इस पर संगीतकार ने तुरंत किसी भी तरह के फर्क की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह तेलुगु या तमिल फिल्म से अलग नहीं है। हर म्यूजिक स्कोर मेरे लिए एक चुनौती होती है। मैं हर स्कोर को ऐसे बनाता हूं जैसे वह मेरा पहला स्कोर हो।

म्यूजिक कंपोजर के साथ सिंगर और एक्टर भी हैं जीवी प्रकाश

जीवी प्रकाश कुमार एक म्यूजिक कंपोजर, सिंगर और एक्टर हैं। उन्होंने 120 से ज्यादा तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। उन्हें 'सूर्यराई पोटरु' के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का नेशनल अवॉर्ड मिला। वे मशहूर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान के भांजे हैं। म्यूजिक के अलावा वो तमिल सिनेमा में एक लोकप्रिय एक्टर भी हैं और अपनी 2015 की फिल्म 'डॉलिंग' के लिए जाने जाते हैं।



पुलिसवालों के प्रति मेरी समझ बहुत बढ़ गई

रियलिटी शो से लेकर टीवी और अब ओटीटी तक शालीन मनोटी ने अपने करियर में लगातार नए मोड़ देखे हैं। उतार-चढ़ाव, चर्चाओं और निजी जिंदगी पर हुई सार्वजनिक बहसों के बीच उन्होंने एक बात नहीं बदली, जहां जरूरी नहीं होता, वहां वह चुप रहना बेहतर है। अपने किरदारों के लिए सख्त अनुशासन अपनाने वाले शालीन मानते हैं कि फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जितना कठिन होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण मानसिक बदलाव भी होता है। पिछले दिनों अपनी वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' के दूसरे सीजन को लेकर काफी चर्चा में रहे। शालीन ने कहा- मेरी जिंदगी के कई फेज पब्लिक डिस्कशन में रहे पर मैंने कोई दूरी नहीं बनाई। दरअसल, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी है। मेरा अपना एक दायरा है और मैं उसे हमेशा मेंटेन करता हूं। मैं हमेशा से ऐसा करता आया हूं। प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह है। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती।

मैंने कोई दायरा बनाने के बारे में अलग से सोचा भी नहीं है। मेरी पब्लिक मेरी सब कुछ है। आज मेरे करोड़ों फॉलोअर्स हैं। अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, उन्हें मेरे बारे में सब पता है। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है और मैं किसी को जज भी नहीं करता। जहां मुझे नहीं बोलना होता, वहां मैं नहीं बोलता और वैसे ही अपनी पब्लिक को भी नहीं बोलता। बाकी मेरे घर में ना मीडिया वाले घुसते और ना ही फैंस क्योंकि सबकी एक सीमा होती है। मेरे लिए फिजिकल और इमोशनल दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल हैं। अगर कोई बोले कि दो महीने के अंदर पूरा लुक बदलना है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने करके देखा है इसलिए कह रहा हूं। फिजिकल के अलावा कई बार मेंटली ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। दरअसल, बोला जाता है कि यह नहीं, वो नहीं खाना है, तीन महीने बाद यह करना है। मैंने भी करीब 110 दिन बहुत डिस्प्लिन से काम किया।

पुलिसवालों के प्रति मेरी समझ बहुत बढ़ गई एक कॉप का कैरेक्टर करने के बाद मेरी उनके प्रति समझ बहुत बढ़ गई है। कई बार हमें लगता है कि एयर होस्टेज का काम सिर्फ पानी और खाना देना है लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब दूसरी तरफ का काम समझते हैं

तो पता चलता है कि वह कितना महत्वपूर्ण है। वह आपातकाल परिस्थितियों में आपकी जान बचाती है। उन्हें मेडिकल नॉलेज भी दी जाती है। इसी तरह, जब पुलिसवाले को देखते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा, यही उनका काम है लेकिन असल में उनका काम बहुत मुश्किल होता है। उसमें सही और गलत की परख करना मुश्किल है। एक पुलिसवाले के लिए, वो भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के लिए यह और कठिन हो जाता है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो होता है, उसे एक सेकेंड में सही और गलत का फैसला करना होता है। कहां गोली मारनी है, हवा में चलानी है, पैर पर हिट करना है, मारना है या नहीं मारना है? यह जजमेंट उसे उसी पल लेना होता है। आप जब इस बात को समझते हो तो पुलिस के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। उन्हें किसी के जीवन के बारे में फैसला लेना पड़ता है। यह बहुत मुश्किल और ट्रिकी सिचुएशन होती है।

अभी तो बहुत सारे बदलाव आने बाकी हैं मेरा सफर रोडीज, टीवी, फिक्शन, डॉस रियलिटी, बिग बॉस, बेकाबू और अब ओटीटी तक आया है। इस सफर में मैं हर फेज के बाद बदल रहा हूं। यहां तक कि जीवन के हर पल में मैं खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहा हूं। इस साल मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सीरियसली

बदल रहा हूं। हर पड़ाव में मुझे बदलाव दिखे हैं। मैंने जब बिग बॉस किया था, वह भी बहुत बड़ा पड़ाव और बदलाव था। आप जब करोड़ों लोगों के सामने एकदम से बाहर आते हो तो वह पल कमाल होता है। मैं टोरंटो में था, वहां अपना शो कर रहा था। हजारों लोग आए थे। मैंने अपने लिए स्टेडियम भरे हुए देखे हैं। मुझे लगा कि वाह क्या बात है। फिर अगले ही पल दिलजीत दोसांझ का शो देख लिया तो मन छोटा हो गया कि अभी जिंदगी में आगे बहुत कुछ पाना बाकी है। अभी तो बहुत सारे चेंजेस आने हैं और मुझे लगता है कि सारे बदलाव अच्छे ही होंगे।

टीवी जो मोहब्बत देता है, वो कोई नहीं दे सकता

टीवी और ओटीटी, दोनों मीडियम अलग हैं। टीवी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। टीवी जो मोहब्बत देता है, वो कोई नहीं दे सकता। इसके जरिए आप हर घर में पहुंच जाते हैं। आज जितना मैं जाना जाता हूं, वह टीवी की वजह से है। वही वेब की एक रिच मार्केट और ऑडियंस है।